ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-1* Issue-12* March- 2017
Anthology : The Research

भूमण्डलीकरण के नये युग में आर्थिक विकास का पूंजीवादी मॉडल

विजय सर्राफ
विभागाध्यक्ष,
राजनीति विभाग,
शा. स्नातकोत्तर महा.,
झालावाड़, राजस्थान

वैशाली बडोलिया
शोध छात्रा,
राजनीति विभाग,
शा. स्नातकोत्तर महा.,
झालावाड़, राजस्थान

सारांश

भूमण्डलीकरण ने विश्व के विभिन्न देशो की अर्थव्यवस्था को जोड़कर वैश्विक गांव की संकल्पना का स्वप्न साकार किया है। आज भूमण्डलीकरण के क्षेत्र में आर्थिक, राजनैतिक के साथ – साथ आतंकवादी, परमाणु प्रसार, पर्यावरण प्रदुषण, मानवाधिकार उल्लंघन जैसी वैश्विक लोकतंत्र की बात होने लगी है। आज के युग में वैश्विक गाँव की बात होने लगी है। वैश्वीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के युग ने शक्ति की संकल्पना को अपनी परिस्थितियों के अनुरुप अनुकूलित किया है। वर्तमान वैश्विक युग में राष्ट्रीय हित की धारण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। अतः कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण के अर्थ में परिवर्तन आया है और सम्पूर्ण विश्व एकता के सूत्र में बधनें के लिए प्रयासरत है।

मुख्य शब्द : वैश्विक गांव, वैश्विक लोकतंत्र, सतत् विकास, नवीन आर्थिक नीति, सूचना तकनीक, मानवाधिकार।

प्रस्तावना

वैश्वीकरण का तात्पर्य उस विश्व व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं और दूरियों से परे एकीकृत आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की सीमाविहीन सक्रियता को वास्तविक मान लेने पर ही बौद्धिक जगत इस निष्कर्ष पर पहूँच पाया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद वि–समीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी जो कि वैश्वीकरण के रूप में हमारे सामने है।

अध्ययन का उद्देश्य

वैश्वीकरण की नये युग में उपायोगिता और प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

भूमण्डलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़कर सम्पूर्ण विश्व को एक वैश्विक गॉव में परिवर्तित करती है। यह मुक्त व्यापार, प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, तीव्र सवृंद्धि पर बल देता है। राज्य की आर्थिक और कल्याणकारी भूमिका को सीमित करना चाहता है।

वैश्वीकरण का औपचारिक उद्भव विशेषकर आर्थिक वैश्वीकरण का 1944 के ब्रेटनवुड्स सम्मेलन से माना जाता है। जिसमें तीव्रता 1991 शीतयुद्ध के अन्त और सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई, इसी कारण आर्थिक वैश्वीकरण के नियमन के लिए 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का आकार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। निरन्तर बढ़ते क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों की संख्या भी वैश्वीकरण के प्रभाव में वृद्धि को प्रदर्शित करती है।

वैश्वीकरण के रूप में आर्थिक क्षेत्र में निजीकरण, उदारीकरण के रूप में वृद्धि नहीं हो रही है, अपितु अन्य क्षेत्रों में वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। यथा –

1. यू.एन.ओ. की बढ़ती संख्या व शक्ति राजनैतिक, वैश्वीकरण के रूप में सामने है।
2. मानवाधिकार आन्दोलन, विश्व नागरिकता आन्दोलन, पर्यावरण आन्दोलन, सूचना अधिकार आन्दोलन आदि रूपों में वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है।
3. सूचना तकनीक के बढ़ते प्रयोग के रूप में मानव व मानव के मध्य बढ़ते सम्पर्क से भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो रही है।
4. नवसामाजिक आन्दोलनों के बढ़ते प्रभाव के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया निरन्तर वैश्विक रूप ले रही है।

उपर्युक्त प्रगति के साथ–साथ वैश्वीकरण के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही है जो इस प्रकार हैं–

(अ) यूनान आर्थिक संकट, व अमेरिकी सब प्राइम संकट जैसी स्थितियॉ,
(ब) विकासशील देशों में संस्कृति व धर्म का प्रभाव व राष्ट्रनिर्माण व राज्य निर्माण की समस्याएँ,
(स) राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय तनाव (जैसे भारत–पाक तनाव),
(द) अमेरिकी प्रभुत्व की नीति,
(य) नव उपनिवेशाद,

इन चुनौतियों के बावजूद वैश्वीकरण का प्रभाव निरन्त बढ़ रहा है, परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण की दिशा को सामाजिक न्याय व 'वैश्विक मानव विकास' के आधार पर निर्धारित किया जाए।

IMF, विश्व बैंक जैसी संस्थाएँ वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक की सहयोगी संस्था IFC का मूल उद्देश्य वैश्वीकरण या पूंजीवाद अपनाने वाले राष्ट्रो को आर्थिक सहायता उपलब्ध करना है। 1980 के दशक में IMF विश्व बैंक जैसीं संस्थाओं नें संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम अपनाया इसके तहत् पूंजीवादी देशों ने वैश्वीकरण अपनाने वाले राष्ट्रों कों आर्थिक सहायता निम्न दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है।

इसी कार्यक्रम के तहत सोवियत संघ को सहायता प्रदान की गई। इसके बावजूद सोवियत संघ का विघटन हुआ और वैश्विकरण और पूँजीवाद पूरे विश्व में प्रभावी होने लगा। पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राष्ट्रों नें वैश्वीकरण को अपनाया। यूरोपीय देशों ने इसे स्वीकारते हुए वर्ष 1992 में मैस्ट्रिच संधि के फलस्वरूप EEC का यूरोपीय संघ में परिवर्तन किया। यह वर्तमान में एकल मुद्रा, एकल संसद , एकल विदेश नीति और एकल रक्षा नीति को अपना रहा हैं।

वैश्वीकरण के प्रसार में गेट के स्थान पर अस्तित्व में आए विश्व व्यापार संगठन नें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। WTO का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार का नियमन वैश्वीकरण के अनुरूप करना है। आज समाजवादी देशों जैसे रूस व चीन ने भी वैश्वीकरण को आर्थिक आधारों पर स्वीकार कर लिया है। तृतीय विश्व क्षैत्रीय आर्थिक संगठन जैसे EU, आसियान, सार्क, नाफ्टा, बिमस्टेक, अफ्रीकन यूनियन, मरर्कोसुद, एण्डोसुद, एडेन समुदाय टीम–9 वैश्वीकरण की नीति को अपनाकर अपना विकास कर रहे है।

भारत जैसे विकासशील देश ने 1991 में नवीन आर्थिक नीति को अपनाकर वैश्वीकरण के अनुरूप, आयात शुल्कों में कमी, कृषि पर मात्रात्मक प्रतिबन्धों को समाप्त किया व पेटेंट व्यवस्था में परिवर्तन कर विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन के चालू खातों को परिवर्तनीय बनाने के बाद पूंजी खातों को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया है।

यद्यपि वैश्वीकरण को अपनाकर विश्व के सभी राष्ट्र सतत् विकास चाहते है। और वे विकास के लिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को एक ओर रखने के लिए तत्पर है किन्तु इससे पूर्व अपना सतत् विकास चाहने वाले राष्ट्रो को कुछ यक्ष प्रश्नों का हल खोज लेना चाहिए कि क्या वैश्वीकरण के तहत आर्थिक उदारीकरण की व्यवस्था एकदम नयी है या इससे पहले भी कोई ऐसी व्यवस्था थी ? क्या यह एक ऐसा मापदण्ड है जिसे पूरी तरह से जीवन मूल्यों तथा सम्पूर्ण वैचारिकी को प्रभावित करने के लिए निर्मित किया गया है ? क्या इसके जरिये पूंजीवादी औद्योगीकरण को विश्वव्यापी बनाने का प्रयास किया जा रहा है या बनाया जा चुका है? मुक्त व्यापार, नियमविहीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध राज्यों की आर्थिक भूमिका को नकार रहे है इसके क्या प्रभाव होते दिखाई दे रहे है? विश्व परिदृश्य में लगभग तीन सदी से जो परिवर्तन दिख रहे है उनका लाभ किसे मिल रहा है? क्या वैश्वीकरण देशों के बीच दूरियों को सकारात्मक तरीके से दूर कर पाया है? क्या मुक्त व्यापार उत्पादन, निवेश, आवागमन, सूचना क्रान्ति, उपभोक्तावादी जीवन मूल्य सारी दुनियॉ को एक रंग में रंगने में कामयाब हुए है?

सामन्तवाद की आर्थिकेत्तर ताकत के आधार पर संचालित व्यवस्था के खिलाफ उभरी पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत के आधार पर आधुनिक पुंजीवादी साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। 1990 के शुरूआती वर्षो में इसने तीसरी दुनियॉ के देशों को प्रभावित कर अपने ईशारे पर रखने का कार्य किया। अब तक आर्थिक तरक्की को चाहने वाले देशों ने पूंजी और बाजार के क्षेत्र में खासी तरक्की की है। विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थाओं ने खासकर दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिकों लेटिन अमेरिकी देशों में पूंजी अर्जन का फार्मूला दिया।

राष्ट्रीय सम्प्रभुता का पूंजी के पक्ष में समर्पण समाज के बहुसंख्यक वर्ग की उत्तरजीविता पर अध्ययन कर रहा है। 21 वीं सदी के पहले दशक की समाप्ति तक भूमण्डलीकरण का भयानक चेहरा साफ हो रहा है। इसका एक पहलू यह है कि परिष्कृत टेक्नोलोजी पर आधारित औद्योगिकरण तो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनियाभर में उसी गति से कृषि का ह्रास हुआ है। खनिज प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से नाजूक परिस्थितिकीतंत्र बिगड़ गया है। पारम्परिक जीविका के साधन खोने के बाद लोग विस्थापितों की जिन्दगी जीने को मजबूर है। कई तो नस्लवादी हिंसा का शिकार हो रहे है। जबकि भूमण्डलीकरण का एक बुनियादी तर्क यह कि जैसे–जैसे यह प्रक्रिया तेज होगी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संतुलित होकर अन्तनिर्भरता बढ़ाएगी और गरीब व वंचित वर्ग को लाभ होगा। उसके जीवन स्तर में सुधार होगा लेकिन दर्दनाक सच है कि इसका विपरीत देखने को मिल रहा है।

प्राकृतिक संसाधन सम्पन्न भू–भाग पर सत्ता परिवर्तन के नाम पर अमेरिका अपना हस्तक्षेप बढ़ाता जा रहा है। आने वाले वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का ताना बाना इस नव पूंजीवादी एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण के साथ अनिवार्यतः जुड़ा रहेगा।

हाल ही के दिनों में स्वयं अमेरिका व यूरोप में वित्तीय संकट से आर्थिक मंदी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अस्थिर हुई। वहाँ बढ़ती बेरोजगारी और मंहगाई के कारण वहाँ की सरकारों पर दबाव बढ़ा कि वह सस्ते

आयात पर रोक लगाए, और अपने किसानों और उद्यमियों को संरक्षण प्रदान करे। कहने का आशय यह है कि स्वयं भूमण्डलीकरण की दुहाई देने वाला अमेरिका व यूरोप अफ्रो एशियाई आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विवश हुए है। अब श्रम, सेवाओं और पूंजी निवेश पर किये गये अनुबंधों पर भी संशय बना हुआ है।

आने वाले वर्षो में इस्लामी कट्टरपंथी और इससे पोषित दहशतगर्दी का मुकाबला भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी नये व पुराने राष्ट्र राज्यों को करना होगा। यह चुनौती मात्र सामरिक नहीं, आर्थिक एवं सांस्कृतिक भी है और इसका असर राष्ट्र राज्य की सम्प्रभुताओं पर अवश्य पड़ेगा। इन सबके चलते परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में मतैक्य कठिन है। यदि भविष्य की पदचाप सुनें तो एक बार फिर महात्मा गांधी और उनके सिद्धान्तों का स्मरण हो आता है।

आज से बहुत समय पूर्व उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का आकलन कर सादा जीवन उच्च विचार का संदेश पूरे विश्व को दिया। अंहिसा, सत्य, अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तत्कालीन समय में हो। यदि भूण्डलीकरण का आवश्यक आधार अर्थव्यवस्था न होकर मानवीय होता तो इसके अनेक फायदे मानव को प्राप्त हो सकते थे।

विकासशील देशों का कहना है कि वैश्वीकरण का एक पहलू श्रम मुक्त प्रवाह भी है परन्तु विकसित देश ''बिजनेस प्रोसस आउटसोर्सिंग'' पर नियत्रंण लगा रहें हैं। विकासशील देशों में श्रम को विकसित देशों में प्रवेश करने से रोक रहें हैं। इनके अनुसार विकसित देश सूचना के मुक्त प्रवाह के नाम पर विकासशील देशों पर अपनी संस्कृति थोप रहें हैं, जिस कारण विकासशील देशों की सास्कृतिक पहचान लुप्त हो रही हैं।

वैश्वीकरण को विकसित देश ''ट्रोजन हॉर्स '' के रूप में विकासशील देशों के लिए प्रयोग कर रहें हैं। अतः वैश्वीककरण एक ऐसा वायरस है जो विकासशील व तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा। निर्भरता मॉडल (केन्द्र – परिधि मॉडल) से जुड़े विद्वानों जैसे दास सन्तोष, आन्द्रे फ्रैंक, वार्लास्तीन, मैरीन आदि का स्पष्ट कहना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विकसित देश और अधिक अमीर विकासशील देश और अधिक गरीब होगें। इसी कारण आज लैटिन अमेरिकी देशों में वैश्वीकरण और इसकी वित्तीय संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया है ताकि वैश्वीकरण के ट्रोजन हॉर्स से बचा जा सकें आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण को इस तरह लागू किया जाए ताकि न्याय व समानता पर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके।

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग का आधार विकसित एवं विकासशील देशों की पारस्परिक निर्भरता है क्योंकि वैश्विक युग में अमीर और गरीब विश्व अलग रहकर लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक न्याय पर आधारित वैश्विक समाज का निर्माण तभी सम्भव है जब विकसित देशों के साथ–साथ विकासशील एवं तृतीय विश्व के देश भी विकास करें। एक खुशहाल विश्व का निर्माण तभी हो सकता है जब विश्व के विभिन्न देशों की पारस्परिक आर्थिक क्रियाऐं, न्याय व समानता पूर्ण एवं शोषण रहित हो।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय हित की अवधारणा में भी परिवर्तन आ रहा है, वर्तमान में राष्ट्र आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए अपनी आंशिक सम्प्रभुता का भी त्याग कर रहे हैं। आज आर्थिक व तकनीकी तत्वों का महत्व बढ़ रहा है। शक्ति सन्तुलन अवधारणा का तात्पर्य बदलकर आर्थिक सन्तुलन हो गया है। सैनिक शीतयुद्ध के स्थान पर आर्थिक शीतयुद्ध का महत्व बढ़ रहा है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा जिसमें सभी राष्ट्र मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा का संकल्प लेते हैं में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज आक्रमण से सुरक्षा के स्थान पर ''आर्थिक सुरक्षा'' इसका प्रमुख मुद्रा बन चुका है अतः आज सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की भूमिका के स्थान पर राष्ट्र विश्व व्यापार सगंठन (WTO) की भूमिका पर बल देते हैं एवं UNO के स्थान पर (EU) (ASEAN) (AU) (NAFTA) को अधिक महत्व दे रहे है। अतः हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के युग ने शक्ति की सकंल्पना को अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया है।

लोकतंत्र के क्षेत्र में देखा जाए तो आज वैश्विक लोकतंत्र की स्थापना के क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब राजनीतिक लोकतंत्र के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना हो। अतः वैश्विक लोकतंत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं का भी लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए। वैश्विक लोकतंत्र की वास्तविक परिणति से ही आतंकवाद, परमाणु प्रसार, पर्यावरण प्रदुषण, मानवाधिकार उल्लंघन जैसी समस्याओं का निदान भी वास्तविक रूप से सम्भव हो सकेगा। आज विश्व में मानवजाति के समक्ष पर्यावरण हास के कारण अनेक समस्याऐं जन्म ले रही हैं। जिसके विरूद्ध चेतन मानव ने संगठित रूप से प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास भी किया है।

वैश्वीकरण का क्षेत्र पर्यावरणीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है। UNCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) में पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सहमति बनी। यह पर्यावरण संरक्षण व सतत् विकास पर विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था बनी है।

ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, अम्लवर्षा, जल प्रदुषण, जैव विविधता में ह्रास, मरूस्थलीकरण, इन सभी समस्याओं के लिए सतत विकास अर्थात विनाश रहित विकास की धारणा को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। विकास एवं पर्यावरण आयोग के अनुसार सतत् विकास ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति के साथ भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण के उपर्युक्त विरोधों का तात्पर्य यह नहीं है कि वैश्वीकरण का प्रभाव समाप्त हो रहा है, आज भी वैश्वीकरण सम्पूर्ण विश्व में अपना प्रभाव जमा रहा है और सम्पूर्ण विश्व को विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में

बदल रहा है। अतः यदि पूंजीवादी देशों द्वारा इसका प्रयोग अपना प्रभुत्व व प्रभाव बढाने के लिए न किया गया होता तो आज भूमण्डलीकरण द्वारा वसुधैव कुटुम्बकम् का आदर्श साकार होता दिखाई देता।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *राजस्थान पत्रिका*
2. *हिन्दुस्तान टाइम्स*
3. *21 वी शताब्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, पुष्पेन्द्र पंत*
4. *अन्डरस्टेण्डिंग ग्लोबल इकोनोमी, रिचर्ड हावार्ड*
5. *वर्ल्ड फोकस, हिन्दु पत्रिकाऐं, दृष्टिकोण मंथन पत्रिका*